Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of February, 2019.

A Memorandum of Understanding (MoU) between the Republic of India and the Korean National Police Agency of the Republic of Korea on combating transnational crime and developing police cooperation was signed during the State visit of Hon'ble Prime Minister of India to Seoul, Korea from 21-22 February, 2019.

2. The Union Home Minister Shri Rajnath Singh and Minister for Women and Child Development, Smt. Maneka Sanjay Gandhi jointly launched the Women Safety initiative of Emergency Response Support System (ERSS) in 16 States/UTs and Mumbai city, on 19.2.2019. People in these states and UTs can now call a single pan India number 112 for any emergency. In addition, Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) and Safe City Implementation Monitoring Portal were also launched.

3. The Government approved the proposal to sign MoU between National Crime Records Bureau and National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) USA for accessing tipline reports pertaining to child pornography for investigation and prosecution of offenders.

4. A Secretary level meeting on Border Management and Security between India and Bhutan was held during 14 -16 February, 2019 in Thimpu (Bhutan).

5. On 27.02.2019, 101 medal for Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation was announced for the year 2018. These include 12 women police officers.

6. Central Government has listed 'Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) and all its manifestations' as terrorist organization involved in terrorism in the First Schedule of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) on 05.02.2019.

7. A meeting of Central Level Committee (CLC) was held under the chairmanship of Special Secretary (Border Management) on 18.02.19 to review financial and physical progress of works undertaken by States under Special Central Assistance scheme.

8. A total of 216.24 km. of Indo Nepal Border Roads have been completed till the end of this month.

9. Enhancement of Risk & Hardship Allowance to CAPFs personnel deployed in the State of J& K and LWE Districts for Anti-naxal operations has been approved.

10. MHA vide letter dated 21.02.2019 conveyed approval of the competent authority to allow non-entitled personnel of CAPF's , AR and NSG to travel by air from Jammu to Srinagar and back on official duty/transfer/tour and leave and also from Delhi to Srinagar and back on official duty/transfer/tour.

11. An amount of Rs. 17.37 Crore has been sanctioned for acquisition of land and Rs 650.62 Crore has been sanctioned for development of infrastructure to the CAPFs. Further this Ministry has approved Rs.27 crore approx. for construction and procurement of the various items under Swachhta Action Plan.

12. An amount of Rs.17.73 crore has been sanctioned as Ex-gratia Compensation to the NOKs of CAPFs.

13. A total Number of 251 Coys of CAPFs were deployed in various States for security of Parliament during Budget Session, maintaining law and order duties for Friday Prayer in Hyderabad City, security arrangements during the visit of VVIP and maintaining law and order at Mathura, Gautam Budh Nagar, Jhansi, Varansi, Gorakhpur, Kumbh Mela, 12th AERO India Show 2019, Jharkhand; Dharna/protest against Hon'ble LG of Puducherry and "Masi Magam" festival; and for maintaining law and order from 22.2.2019 till further orders in J &K.

14. Sanction for prosecution for filing the charge sheet against 31 accused persons was accorded under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for terrorist and anti-national activities.

15. Instructions of the President for promulgation of the Andhra Pradesh (Andhra Area) Inams (Abolition and Conversion into Ryotwari) (Amendment) Ordinance, 2018 have been conveyed to the State Government on 19.02.2019.

16. NOC has been issued for change in the name of village 'Durjanpur' as 'Shivdham' in District, Katni, Madhya Pradesh.

17. 02 advisories were issued to the State Government / CAPFs to sensitize them to counter the LWE activities in the LWE affected areas.

18. Authorisation for Rs.195,95,23,594 and provisioning and expenditure sanction for Rs.418,01,20,885 has been issued to the CAPFs for purchase of mine protected vehicles, bullet proof vehicles & jackets, ambulance etc. Further, expenditure sanction for Rs.16,84,24,459/- has been issued to NSG for purchase of 7 remotely operated vehicle.

19. The National Register of Citizens (NRC) 1951 in Assam is being updated under the provisions of Citizenship Act, 1955. The process of receipt of claims and objections on the draft NRC has been completed on 31.12.2018. The verification process has started from February 15, 2019. The final NRC will be published by 31.07.2019 after the disposal of claims and objections as per the directions of the Hon'ble Supreme Court of India.

फरवरी, 2019 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के 21-22 फरवरी, 2019 तक सियोल, कोरिया के राजकीय दौरे के दौरान राष्ट्रपारीय अपराध को रोकने तथा पुलिस सहयोग विकसित करने के बारे में भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य की कोरियन नेशनल पुलिस एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2. केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी ने 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा मुम्बई शहर में आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) की महिला सुरक्षा पहल का दिनांक 19.02.2019 को संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोग अब किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरे भारत में एक ही नम्बर 112 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यौन अपराधों हेतु जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) तथा सुरक्षित शहर कार्यान्वयन मॉनीटरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।

3. सरकार ने अपराधियों की जांच और अभियोजन के लिए बाल अश्लील साहित्य (चाईल्ड पोर्नोग्राफी) से संबंधित टिपलाइन रिपोर्टों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तथा नेशनल सेंटर फॉर मीसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमइसी) यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

4. भारत और भूटान के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में 14-16 फरवरी, 2019 के दौरान सचिव स्तरीय बैठक थिम्पू (भूटान) में आयोजित की गई।

5. जांच में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2018 हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए दिनांक 27.02.2019 को 101 मेडलों की घोषणा की गई। इनमें 12 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

6. केन्द्रीय सरकार ने आतंकवाद में शामिल 'तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन (टीयूएम) तथा इसके सभी गुटों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की प्रथम अनुसूची में दिनांक 05.02.2019 को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।

7. विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने के लिए विशेष सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2019 को केन्द्र स्तरीय समिति (सीएलसी) की बैठक आयोजित की गई ।

8. इस माह के अंत तक कुल 216.24 कि.मी. भारत-नेपाल सीमा सड़क का निर्माण पूरा किया गया है।

9. जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए नक्सल-रोधी अभियानों हेतु जोखिम एवं कठिनाई भत्ते में वृद्धि को अनुमोदित किया गया है।

10. गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स तथा एनएसजी के गैर-हकदार कार्मिकों को सरकारी ड्यूटी/स्थानान्तरण/दौरे तथा अवकाश पर जम्मू से श्रीनगर और वहां से वापस होने तथा सरकारी ड्यूटी/स्थानान्तरण/दौरे पर दिल्ली से श्रीनगर और वहां से वापस होने के लिए हवाई यात्रा की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दिनांक 21.02.2019 के पत्र के तहत प्रदान किया।

11. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु 17.37 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है तथा अवसंरचना के विकास हेतु 650.62 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य और विभिन्न मदों के प्रापण के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है।

12. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकटतम रिश्तेदारों को अनुग्रह मुआवजा के रूप में 17.73 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

13. बजट सत्र के दौरान, संसद की सुरक्षा, हैदराबाद शहर में शुक्रवार की नमाज हेतु कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी ड्यूटी, अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजाम और मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, कुम्भ मेला, 12वें एयरो इंडिया शो 2019, झारखण्ड; पुडुचेरी के माननीय उप राज्यपाल के विरुद्ध धरना/प्रदर्शन तथा ''मासी मागम'' त्यौहार के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने; और जम्मू एवं कश्मीर में दिनांक 22.02.2019 से अगले आदेश तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 251 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में तैनात किया गया।

14. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 31 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

15. आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम्स (उन्मूलन तथा रयोतवारी में परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रख्यापन हेतु राज्य सरकार को दिनांक 19.02.2019 को राष्ट्रपति के अनुदेश संसूचित किए गए हैं।

16. मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 'दुर्जनपुर' का नाम बदलकर 'शिवधाम' करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

17. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए जागरूक बनाने हेतु राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 02 परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

18. बारूदी सुरंग से सुरक्षा प्रदान करने वाले वाहनों, बुलेट प्रूफ वाहनों तथा जैकेटों, एम्बुलेंस आदि की खरीद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 195,95,23,594/- रुपए का प्राधिकार तथा 418,01,20,885/- रुपए के प्रोविजनिंग एवं व्यय की स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, दूर से प्रचालित किए जाने वाले 07 वाहनों की खरीद के लिए एनएसजी को 16,84,24,459/- रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

19. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) 1951 को नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत अद्यतन किया जा रहा है। एनआरसी के मसौदे पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 31.12.2018 को पूरी कर ली गई है। सत्यापन प्रक्रिया 15 फरवरी, 2019 से आरंभ हो गई है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटान के बाद अंतिम रूप से एनआरसी को 31.07.2019 तक प्रकाशित किया जाएगा।

****